Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to undertake caste census in Census 2021.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा बताया गया है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी । इस सूचना से हम सब स्तब्ध एवं दुखी हैं क्योंकि हमारी केंद्र सरकार पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण के लिए जानी जाती है । यह सूचना निराशाजनक है ।

आज देश के अधिकांश लोग जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हैं । जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उनके फायदे की योजनाएं कैसे बनेगी । जाति आधारित जनगणना से एससी, एसटी के अलावा भी अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी । बिहार विधान मंडल ने 18 फरवरी 2019 एवं पुनः 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केन्द्र सरकार को भेजा गया था । मेरा सरकार से आग्रह है कि जातिगत जनगणना यथाशीघ्र कराई जाए ।